प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 19 जून, 2017

विषय- जिला कारागार, कासगंज के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 18615/नम-1/76(2), दिनांक- 02 जून,2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि जिला कारागार, कासगंज के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-214/22-4-10-48(28)/08, दिनांक 15.02.2010 द्वारा रू0 5887.52 लाख की लागत पर एवं शासनादेश संख्या-644/22-4-13-48(28)/08, दिनांक 19.06.2013 द्वारा रू0 7675.37 लाख की लागत पर प्रथम पुनरीक्षित तथा शासनादेश संख्या-66/2015/1540/22-4-14-48(28)/08, दिनांक 17.03.2015 द्वारा रू0 11314.58 लाख की लागत पर द्वितीय पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार उक्त निर्माण की कुल लागत के सापेक्ष 05 प्रतिशत धनराशि को रोकते हुए अब तक रू0 10748.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, कासगंज के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 5,65,73,000/-(रूपया पॉच करोड़ पैंसठ लाख तिहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग एवं कार्य दिनांक 30.09.2017 तक कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.02.2010, पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.06.2013 एवं 17.03.2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 02.01.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-42/2017/467(1)/22-4-17-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कासगंज।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in